

प्रेषक,

जयदेव सिंह,
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 12 मार्च, 2014

विषय- जिला देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर में स्थापित एक-एक स्थायी लोक अदालत में सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-74/XXXVI(1)/2013-23-एक(5)/2005 टी0सी0 दिनांक 05.03.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर में स्थापित एक-एक स्थायी लोक अदालत हेतु सृजित 10 अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये दिनांक 01.03.2014 से दिनांक 28.02.2015 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त न्यायालयों/पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या 24-एक(5) छत्तीस(1)/2005-23-एक(5)/2005 दिनांक 09.11.2005 द्वारा किया गया है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-10-स्थायी लोक अदालत-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-1270/76-दस दिनांक 20 जुलाई 1968 सपटित कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 07-11-1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं।

भवदीय

(जयदेव सिंह)
प्रमुख सचिव

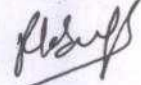
क्रमशः.....2

संख्या- 68 (1)/XXXVI(1)/2014-23 एक(5)/2005 टी0सी0 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा देहरादून।
- 2- महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 3- जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
- 5- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से



(राकेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव